3 लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता के प्रतीक PM मोदी

5 आंतरिक संघर्षों के बावजूद कांग्रेस के प्रमुख नेता

6 छात्राओं का यौन उत्पीड़न एवं आत्महत्याएं

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 12 प्रति सोमवार, 28 जुलाई 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मध्यप्रदेश भाजपा में संगठन परिवर्तन की बयार, हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति के बाद बड़े बदलाव की तैयारी

निगम मंडल के अध्यक्ष पद के नाम को लेकर आगे पीछे हो रहे मंत्री, नेता

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष पद पर हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति के बाद संगठनात्मक हलचलें तेज हो गई हैं। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें अध्यक्ष बनाकर यह संकेत दिया है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर 2029 के लोकसभा चुनाव तक भाजपा प्रदेश में नई रणनीति, नई ऊर्जा और युवा नेतृत्व के सहारे उतरेगी। खंडेलवाल के अध्यक्ष बनते ही संगठन में परिवर्तन की बयार चल पड़ी है। भाजपा और संघ ने मिलकर संगठन के पुनर्गठन की योजना तैयार कर ली है, जिसके तहत प्रदेश भर में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 2020 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी और कांग्रेस के जो विधायक कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आये थे उन्हें बैंगलूरू ले जाया गया था। इसकी पूरी जिम्मेदारी खंडेलवाल के पास थी। बैंगलूरू में खंडेलवाल को ही इन नेताओं की देखभाल करने का जिम्मा दिया और उस पर वह खरे भी उतरे। शायद इसी का ईनाम पार्टी ने उन्हें दिया है।

खंडेलवाल को अध्यक्ष बनाने के पीछे मकसद

हेमंत खंडेलवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रहे दिवंगत मनोहर खंडेलवाल के पुत्र हैं। वे प्रदेश भाजपा और संघ की कार्यपद्धति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। संगठन के जानकारों का मानना है कि खंडेलवाल को अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने प्रदेश में युवा नेतृत्व, साफ-सुथरी छवि, समन्वयकारी

कार्यशैली और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति पूर्ण निष्ठा को प्राथमिकता देने का संकेत दिया है। उनके माध्यम से पार्टी गुटबाजी को नियंत्रित कर संगठन को चुनावी मोड में लाना चाहती है। साथ ही यह नियुक्ति मालवा-निमाड़ के जातीय समीकरणों को भी साधने की दिशा में अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह क्षेत्र भाजपा का पारंपरिक गढ़ रहा है और हालिया चुनावों में यहां पार्टी को अप्रत्याशित चुनौतियां झेलनी पड़ी थीं।

खंडेलवाल की टीम में होंगे बड़े बदलाव

प्रदेश अध्यक्ष पद संभालते ही हेमंत खंडेलवाल ने संकेत दे दिया है कि संगठन में अधिक क्रियाशील, समर्पित और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार खंडेलवाल अपनी नई कार्यकारिणी में कई पुराने चेहरों को बदल सकते हैं। (शेष पेज 2 पर)

चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के रावणराज के अंत की शुरुआत

सबसे पहले जगत विजन ने ही उजागर किया था भूपेश बघेल और चंडाल चौकड़ी का भ्रष्टाचारी तंत्र

-विजया पाठक

भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू को ईडी ने शराब घोटाला में गिरफ्तार कर लिया है। अब तो यही लगता है कि ईडी निश्चित तौर पर तमाम घोटालों के मुख्य साजिशकर्ता भूपेश बघेल तक पहुंच चुकी है, बस गिरफ्तारी की देर है। मैं अपनी पत्रिका और लेखन से 2021 से इन घोटालों को उजागर कर रही हूँ। उसमें असली कार्यवाही अब जाकर हुई है। कोयला, महादेव सट्टा समेत अन्य बड़े घोटालों में भी इनकी गिरफ्तारी जरूर होगी। मैं और मेरा परिवार भूपेश बघेल का वो दमन कभी नहीं भूल सकता है। उस समय मेरे घर के सामने छत्तीसगढ पुलिस मेरी और मेरे परिवार की

अब बघेलमुक्त होना चाहिए कांग्रेस

गिरफ्तारी की जुगत में लगी रहती थी। बाप-बेटे की खास सौम्या के दबाव में मेरे खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए, पर इनके जुल्म बढ़ने के साथ मेरी कलम की धार बढ़ती चली गई थी। उस दौर में छत्तीसगढ़ में किसी पत्रकार या विपक्षी नेता की इनके ख़िलाफ़ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। खैर, आखिर में मेरी कलम की जीत हुई।

चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी बघेल परिवार और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए गंभीर झटका है। राज्य में कांग्रेस की साख और राजनीतिक भविष्य पहले ही संदेह के घेरे में था जिसका कारण भूपेश सरकार थी। (शेष पेज 3 पर)

जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफाः लोकतंत्र, राजनीति और संभावनाओं पर बड़ा सवाल

कहीं शिवराज सिंह चौहान पर की गई टिप्पणी के बाद दबाव में आकर तो धनखड़ ने नहीं दिया इस्तीफा

-विजया पाठक

देश की राजनीति उस समय चौंक गई, जब भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि यह फैसला उनका नहीं बल्कि सरकार का है। जबरन उनसे इस्तीफा लिया गया हो। धनखड़ का इस्तीफा देश की संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों और भाजपा के आंतरिक समीकरणों पर भी कई बड़े प्रश्नचिन्ह खड़े कर गया। धनखड़ का इस्तीफा इसलिए भी ज्यादा चौंकाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि वे लंबे समय तक भाजपा के निष्ठावान नेता रहे, किसान परिवार से आने के कारण जमीनी राजनीति की मजबूत पकड़ रखते थे और उन्हें भविष्य में भाजपा के बड़े चेहरे के रूप में भी देखा जाता था। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर धनखड़ इतने नाराज क्यों हुए कि उन्हें उपराष्ट्रपति जैसा गरिमामय पद भी छोड़ना पड़ा?

लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय

धनखड़ का इस्तीफा भारतीय लोकतंत्र के लिए कई मायनों में चिंताजनक संकेत है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पद संविधान की आत्मा माने जाते हैं। इन पदों पर बैठे व्यक्ति से अपेक्षा होती है कि वे निष्पक्ष, गरिमामय और सरकार तथा विपक्ष दोनों के साथ समन्वय बनाए रखें। (शेष पेज 5 पर)

मध्यप्रदेश भाजपा में संगठन परिवर्तन की बयार, हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति के बाद बड़े बदलाव की तैयारी

(पेज 1 का शेष)

उनकी योजना युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति-जनजाति मोर्चा सहित सभी प्रकोष्ठों में नये पदाधिकारियों को शामिल करने की है। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी बताते हैं कि खंडेलवाल नेतृत्व में जल्द ही प्रदेश कार्यसमिति, जिला कार्यकारिणी और मंडल स्तर तक व्यापक फेरबदल देखने को मिलेगा। यह बदलाव आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण होगा।

नेताओं और मंत्रियों में लगी दौड़

प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही निगम-मंडल, प्राधिकरण और आयोगों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदों को लेकर रस्साकशी भी तेज हो गई है। मंत्री, विधायक और संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेता अपने-अपने करीबियों के नाम दिल्ली और भोपाल तक पहुंचाने में लगे हैं। हर नेता चाहता है कि उसका समर्थक किसी न किसी निगम-मंडल में नियुक्त हो जाए, ताकि राजनीतिक प्रभाव बना रहे। इन नियुक्तियों को लेकर मंत्रालय, प्रदेश भाजपा कार्यालय और मंत्रियों के बंगलों पर समर्थकों की भीड़ जुटने लगी है। कुछ नेता संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए खंडेलवाल के समक्ष भी अपने लोगों के नाम की पैरवी कर रहे हैं। नियुक्तियों के माध्यम से मंत्रियों और विधायकों का यह भी प्रयास है कि समर्थक वर्ग को संतुष्ट रखा जाए और भविष्य में संगठन के भीतर उनका दबदबा कायम रहे।

भाजपा संगठन और संघ की योजना

भाजपा और संघ नियुक्तियों को केवल राजनीतिक संतुष्टि के नजरिए से नहीं देख रहे। संघ का मानना है कि निगम-मंडल के पदों पर ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जो वैचारिक रूप से मजबूत, जनसेवाभावी और संगठन के प्रति पूर्ण समर्पित हों। इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं- ये नियुक्तियां कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने और पार्टी के प्रति निष्ठा को बनाए रखने का माध्यम हैं। नियुक्त व्यक्ति जब जनता के बीच सामाजिक, शैक्षिक

और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करता है, तो संगठन का आधार और मजबूत होता है। इसीलिए संघ और भाजपा संगठन मिलकर नियुक्तियों की सूची तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रदेश संगठन और संघ के समन्वय से ही अंतिम निर्णय होगा।

संगठन के पुनर्गठन का खाका तैयार

हेमंत खंडेलवाल ने अध्यक्ष पद संभालते ही स्पष्ट कर दिया है कि उनका फोकस "पार्टी विद डिफरेंस" के सिद्धांत को जमीन पर उतारने का होगा। वे सभी मोर्चों को सक्रिय कर बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाना चाहते हैं। प्रदेश भाजपा सूत्रों का कहना है कि खंडेलवाल संगठन में ऐसे चेहरों को लाएंगे जो पार्टी का विचार, तकनीक के उपयोग, डिजिटल आउटरीच और सोशल मीडिया रणनीति में दक्ष हों। भाजपा अब मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी डिजिटल प्रशिक्षण देने की योजना बना रही है, ताकि सोशल मीडिया पर विपक्ष के प्रचार का तुरंत और तथ्यात्मक जवाब दिया जा सके। खंडेलवाल स्वयं टेक्नोलॉजी-सेवी नेता माने जाते हैं, इसलिए उनकी टीम में आईटी और सोशल मीडिया विशेषज्ञों को भी जगह दी जा सकती है।

संघ का विशेष फोकस

संघ का मानना है कि 2029 की तैयारियां अभी से शुरू करनी होंगी। संघ के वरिष्ठ प्रचारकों ने हाल ही में अलग-अलग विभागों और संगठनों के साथ बैठकें कर यह फीडबैक लिया कि कहां पर संगठन कमजोर पड़ रहा है, किस जिले में पार्टी के खिलाफ असंतोष पनप रहा है और किन नेताओं के कारण कार्यकर्ता दूरी महसूस कर रहे हैं। यह पूरा फीडबैक प्रदेश नेतृत्व के पास पहुंच चुका है। खंडेलवाल की कार्यकारिणी गठन में संघ की राय अहम होगी और ऐसे नाम शामिल किए जाएंगे, जो केवल पद के लिए नहीं बल्कि संगठन की विचारधारा के प्रचार के लिए भी कार्य करें।

निगम-मंडल नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय जल्द

भाजपा के सूत्रों का कहना है कि अगस्त के पहले सप्ताह तक निगम-मंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सूची जारी कर दी जाएगी। सूची में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही युवा कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में मौका मिलेगा, ताकि संगठन का भविष्य मजबूत हो। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल की जोड़ी इस सूची को अंतिम रूप देने में जुटी है। कुछ बड़े नेताओं के नाम भी इस बार सूची में शामिल हो सकते हैं, जिन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था लेकिन संगठन में उनकी स्वीकार्यता है। हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति ने मध्यप्रदेश भाजपा में संगठनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति दे दी है। आने वाले दिनों में उनकी कार्यकारिणी, निगम-मंडल नियुक्तियों और संगठन के पुनर्गठन के फैसले यह तय करेंगे कि भाजपा 2029 की चुनौती के लिए कितनी तैयार है। फिलहाल भाजपा और संघ, दोनों की निगाहें खंडेलवाल पर टिकी हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली ही यह तय करेगी कि प्रदेश भाजपा 'अजेय संगठन' के अपने लक्ष्य को किस हद तक हासिल कर पाती है।

सौरभ द्विवेदी ने अपनी काबिलियत से किया मुकाम हासिल

कलम के सिपाही

सौरभ द्विवेदी, भारतीय पत्रकार और द लल्लनटॉप के संस्थापक संपादक हैं। द लल्लनटॉप, इंडिया टुडे ग्रुप के स्वामित्व वाला एक हिंदी समाचार और मीडिया वेब पोर्टल है। सौरभ अपनी विशिष्ट, सरल और बोलचाल की भाषा में समाचार प्रस्तुत करने की शैली के लिए जाने जाते हैं। वे द लल्लनटॉप YouTube चैनल पर कुछ लोकप्रिय शो भी होस्ट करते हैं। सौरभ ने अपनी शुरुआती शिक्षा पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में प्राप्त की। द लल्लनटॉप के साथ, उन्होंने राजनीतिक कवरेज और नए जमाने की लेखन शैली के साथ एक लोकप्रिय डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है। सौरभ द्विवेदी, "द लल्लनटॉप" नामक हिंदी समाचार आउटलेट के संस्थापक और प्रधान संपादक हैं। वह एक अनुभवी पत्रकार हैं जिन्होंने इंडिया टुडे, दैनिक भास्कर और स्टार न्यूज जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है।

सौरभ द्विवेदी की शुरुआती शिक्षा कानपुर के एक बोर्डिंग स्कूल से दसवीं और कानपुर से ही जुगल देवी सरस्वती विद्या मंदिर से बारहवीं की पढ़ाई पूरी की।12वीं की पढ़ाई खत्म करने के बाद सौरभ द्विवेदी ने दयानंद वैदिक कॉलेज से स्नातक (गणित) में डिग्री लिए, जिसमें वो सफल रहे। अब आगे वो M.A करने की सोचे जिसके लिए वे जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में प्रवेश लिया और यहीं से पी.एच.डी (PHD) भी की। M.A करने के बाद दिल्ली से IIM (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन) में डिप्लोमा किया। सौरभ द्विवेदी की पढ़ाई अभी तक रुकी नहीं थी। आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हिंदी साहित्य में M.phil की डिग्री उत्तीर्ण की।

उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव हासिल किया है। उनकी पत्रकारिता यात्रा नवभारत टाइम्स से शुरू हुई, जिसके बाद वे दैनिक भास्कर में समाचार संपादक के रूप में शामिल हुए। 2013 में, उन्होंने इंडिया टुडे समूह में प्रवेश किया और 2016 में द लल्लनटॉप की स्थापना की। सौरभ द्विवेदी को उनकी स्पष्ट और प्रभावशाली बोलने की शैली के लिए जाना जाता है, जो उन्हें अन्य पत्रकारों से अलग बनाती है। RSS के शिशु मंदिर में पढ़ाई की। बचपन में RSS की शाखाओं में गये। पिता रविकांत द्विवेदी ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। JNU में वामपंथी गुट में शामिल हुए। वामपंथी बनकर लोकप्रियता हासिल की, हमेशा कुर्ता और गमछा पहने नजर आये। सौरभ द्विवेदी एक ऐसे परिवार में जन्मे, जिसमें से लगभग सदस्य राजनीति से जुड़े हुए थे। सौरभ के दादाजी माता प्रसाद द्विवेदी जो कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। इनके पिता रविकांत द्विवेदी बी.जे.पी के सदस्य और एक प्रोफेसर भी थे। सौरभ द्विवेदी को 2017 में डीजी पब पुरस्कार और 2019 में सर्वश्रेष्ठ एंकर अवार्ड (डिजिटल न्यूज चैनल पर) मिला। लल्लनटॉप के 19 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इसकी शुरुआत साल 2016 में हुई थी जो अब तक के न्यूज चैनल्स में नंबर वन पे आता है।

चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के रावणराज के अंत की शुरुआत

हसदेव जंगल को काटने का सौदा तो भूपेश ने ही किया था, राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद रुकी थी कटाई

(पेज 1 का शेष)

अब पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने पार्टी की बची-खुची विश्वसनीयता को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। चैतन्य को ईडी ने गिरफ्तारी का जो तरीका अपनाया उससे साफ है कि एजेंसी के पास ठोस सबूत हैं। भूपेश बघेल पर पहले से ही कई प्रकार के भ्रष्टाचार, अवैध उगाही, खनन माफिया से सांठगांठ, शराब, कोयला, महादेव सट्टा घोटाले जैसे संगीन आरोप लगे हैं। ईडी और आयकर विभाग की लगातार छापेमारी से यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य में उनके शासन के दौरान एक ऐसा तंत्र खड़ा किया गया, जिसमें सत्ता का उपयोग निजी हितों के लिए किया गया।

सराहनीय है ईडी की कार्यवाही

ईडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बघेल परिवार पर जो कार्यवाही की है वह सराहनीय है। यह उन लोगों को भी जवाब है जो कहते थे कि ईडी कुछ नहीं कर रही है और बघेल परिवार को बचा रही है। आखिरकार ईडी ने अपनी कार्यवाही को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया है।

पत्रकारों को झेलना पड़ी प्रताड़ना, हुई थी गिरफ्तारी

भूपेश बघेल का कार्यकाल कई मायनों में विवादों से घिरा रहा। उन्होंने सत्ता में रहते हुए पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर भी दबाव बनाया। कई पत्रकारों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मीडिया पर इस प्रकार का शिकंजा लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। बघेल सरकार में स्वतंत्रता बुरी तरह कुचली गई।

एक नहीं कई घोटालों के सरगना हैं बघेल

जगत विजन ने वर्ष 2021 से ही भूपेश बघेल और चंडाल चौकड़ी के खिलाफ लिखना आरंभ किया था। उनकी एक के बाद एक सभी परते उधेड़ी। यही कारण है कि आज ईडी और आयकर विभाग की टीमों ने बघेल की नींद उड़ा दी है। हजारों करोड़ के घोटालों की परतें जब खुलीं तो आम जनता के टैक्स के पैसे के दुरुपयोग का भयावह सच सामने आया। राज्य की गरीब जनता, आदिवासी, किसान और मजदूर तबका जिन योजनाओं का लाभ लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, उन्हीं योजनाओं के पैसों को भ्रष्टाचार के जरिये डकार लिया गया। यह सत्ता के दुरुपयोग की पराकाष्ठा कही जाएगी। भूपेश बघेल के शासन में ऐसा तंत्र बना, जहां अधिकारी, ठेकेदार, माफिया और राजनीतिक नेतृत्व – सभी की साझा मिलीभगत से पैसे का अवैध खेल चलता रहा।

आखिर कब खुलेगी आलाकमान की आंखें

अब प्रश्न उठता है कि कांग्रेस आलाकमान आखिर कब तक आंखों में पट्टी बांधे बैठेगा? गांधी परिवार और कांग्रेस नेतृत्व पहले भी राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली पर चुप्पी साधे रहा, जिसका परिणाम पार्टी के लिए विनाशकारी साबित हुआ। छत्तीसगढ़ में भी आलाकमान ने भूपेश बघेल को खुली छूट दी, जिसका नतीजा आज पूरे देश के सामने है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि कांग्रेस के गिरते नैतिक मूल्यों और भ्रष्ट आचरण के संस्थागतकरण का प्रतीक है। यदि आलाकमान ने समय रहते आत्ममंथन नहीं किया तो आगामी समय में पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। अपनी सरकार के पांच साल में भूपेश और उनकी चौकड़ी ने कांग्रेस नेता को कमजोर करने की पूरी कोशिश की यहां तक विधानसभा चुनावों में अपने नेताओं को हरवाने का काम किया। अब प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव जैसे कददावर को भी बघेल की करतूतों के विषय में आलाकमान को अवगत कराना चाहिए कि कैसे बघेल पार्टी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। निश्चित रूप से यदि प्रदेश से बघेल जैसे नेता की छुट्टी होती है तो प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। मजे हुए इन नेताओं को बघेल का बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहिए।

राज्य के विकास को बघेल ने किया प्रभावित

भूपेश बघेल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की पहचान एक भ्रष्टाचारग्रस्त, माफिया संचालित और भययुक्त राज्य के रूप में बन गई। इससे राज्य की प्रतिष्ठा, निवेश वातावरण और विकास की गति– सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

छत्तीसगढ में कांग्रेस के नैतिक पतन के जिम्मेदार हैं भूपेश बघेल

अब सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस आलाकमान के समक्ष यह है कि क्या वह भूपेश बघेल जैसे नेताओं के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेगा या चुप्पी साधे रखेगा? कांग्रेस का भविष्य उन राज्यों में अब भी सुरक्षित है, जहां संगठन मजबूत और नेतृत्व ईमानदार है। लेकिन जिन राज्यों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद की जड़ें गहरी हो चुकी हैं, वहां पार्टी का उभर पाना असंभव होगा। आने वाले लोकसभा चुनाव और उसके बाद की राज्य राजनीति में छत्तीसगढ़ का यह घटनाक्रम निर्णायक भूमिका निभाएगा।

हमारी सरकार मोदी की गारंटी को तेजी से लागू कर रही है: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने घोषणा को प्राथमिकता से पूरा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में विगत दिवस तपकरा प्रवास के दौरान फरसाबहार में विश्राम गृह बनाने की घोषणा की थी, जिसके लिए 1 करोड़ 72 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति भी दे दी हैं। गौरतलब है कि उक्त कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने तपकरा को नगर पंचायत बनाने, तपकरा स्थित खेल स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए देने और फरसाबहार में विश्राम गृह निर्माण करने की भी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयास से आम जनता को अधिकांश कार्यों के लिए राजस्व विभाग की जरूरत पड़ती है। तहसील कार्यालय खुलने से इसका लाभ यहां के नागरिकों मिल रहा है। साय ने कहा कि हमारी सरकार मोदी की गारंटी को तेजी से लागू कर रही है। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए। उन्होंने कहा कि आवास प्लस प्लस के तहत जिसके पास 5 एकड़ असिंचित भूमि या 2.50 एकड़ सिंचित भूमि, टू व्हीलर और 15 हजार की आमदनी है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया था। महिलाओं को सशक्त बनाने महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों की आमदनी में इजाफा के लिए तेंदू पत्ता प्रति मानक बोरा 5500 रुपए किया गया है। ग्रामीणों को गांव में ही बैंकिंग की सुविधा मिले इसके लिए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। आगामी पंचायत दिवस को सभी ग्राम पंचायतों में इसे शुरू करने की योजना है। मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप

फरसाबहार में विश्राम गृह की स्वीकृति मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों में हर्ष व्याप्त है।

वैश्विक मंच पर प्रभावशीलता, लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता के प्रतीक बने हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर प्रभावशीलता, लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता के प्रतीक बने हुए हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सितंबर 2021 से लगातार इस रेटिंग में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। यह उनकी अडिग नेतृत्व शैली, दूरदर्शी नीतियों और राष्ट्रहित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का प्रमाण है, जो न केवल भारत को नई ऊँचाइयों तक ले जा रही है, बल्कि विश्व समुदाय में भी भारत की सशक्त, प्रगतिशील और आत्मनिर्भर छवि को स्थापित कर रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह वैश्विक सम्मान भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक है। उनका नेतृत्व केवल भारत को नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था को एक नई दिशा दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज वैश्विक मंच पर शांति, विकास और मानवता की आवाज बनकर उभरा है। उनका यह स्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा, मजबूत कूटनीति और जन-जन के साथ सीधे जुड़ाव को भी रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि देशवासियों के लिए एक गौरवशाली क्षण है जो दर्शाती है कि एक उभरते हुए राष्ट्र के रूप में भारत का भविष्य दूरदर्शी नेतृत्व में पूर्णतः सुरक्षित है।

भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है बिजावर नगर परिषद

आम आदमी पार्टी का बड़ा खुलासा

-संवाददाता

जगत प्रवाह. बिजावर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव, अमित भटनागर ने कहा कि बिजावर नगर पंचायत में नया बस स्टैंड बनाने के नाम पर 01 करोड़ रुपये के घोटाले की जानकारी सामने आई है। बिना टेंडर, बिना स्वीकृति 70 लाख रुपये की मोरम पहले ही डलवाई गई। अब उसे वैध ठहराने के लिए अचानक टेंडर प्रक्रिया चलाई जा रही है। पूरा मामला जनधन की खुली लूट है। आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों व कार्यकर्ताओं के साथ अनुविभागीय अधिकारी (SDM), बिजावर को ज्ञापन सौंपा। आप की मांगें हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाये, दोषियों पर आपराधिक कार्यवाही हो, जब तक जांच न हो टेंडर प्रक्रिया रोकी जाए, यदि 7 दिन में कार्यवाही नहीं हुई तो जन आंदोलन छेड़ा जाएगा।

सम्पादकीय

देश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश

देश के विभिन्न हिस्सों में इस समय सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की जा रही है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने जहां खेती के लिए संजीवनी का कार्य किया है, वहीं दूसरी ओर बाढ़, भूस्खलन, मकान गिरने, यातायात बाधित होने और जनजीवन अस्त-व्यस्त होने जैसी समस्याएं भी उत्पन्न कर दी हैं। सामान्य से अधिक वर्षा एक ओर कृषि और जल भंडारण की दृष्टि से सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसके दुष्परिणामों की अनदेखी करना भी घातक होगा।

भारत की जलवायु मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। भारतीय कृषि व्यवस्था का बड़ा हिस्सा अब भी वर्षा आधारित है। सामान्य से अधिक वर्षा से नदियों, तालाबों और जलाशयों में पानी का भंडारण बढ़ा है। इससे रबी सीजन के लिए सिंचाई सुनिश्चित होगी। साथ ही पेयजल संकट से जूझ रहे गांवों और शहरों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में कई बड़े बांधों का जलस्तर उनकी क्षमता के करीब पहुंच चुका है, जो ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक उपयोग के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। यह स्थिति हमें यह भी बताती है कि मानसून अब भी भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की धुरी बना हुआ है।

परंतु इस सकारात्मक पक्ष के साथ ही इसके खतरनाक दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने भूस्खलन और मकान गिरने की घटनाओं को बढ़ाया है। सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मुश्किलें बढ़ी हैं। राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जलभराव की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। खेतों में पानी भर जाने से खरीफ फसलों को नुकसान पहुँचा है। धान, सोयाबीन, मक्का और मूंगफली की फसलें प्रभावित हुई हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालयों से संपर्क कट गया है। निचले इलाकों में बसे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। पशुधन का नुकसान और संक्रामक रोगों का खतरा भी बढ़ा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की असामान्य सक्रियता का बड़ा कारण वैश्विक जलवायु परिवर्तन, समुद्री सतह के तापमान में बढ़ोतरी, एलनीनो और ला नीना जैसी स्थितियों का बदलता चक्र है। पिछले दो दशकों में मानसून के व्यवहार में अस्थिरता स्पष्ट दिखने लगी है। कभी आत्यधिक बारिश तो कभी भयंकर सूखा। इसका सीधा असर किसानों की आय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास दर पर पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारी पुख्ता रखें। भविष्य में हमें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के प्रति अपनी नीतियों में सुधार लाना होगा। शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या निरंतर बढ़ रही है, जिसका प्रमुख कारण है अनियोजित विकास, अवैध कब्जे, जल निकासी तंत्र का अभाव और नदियों-नालों का अतिक्रमण। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को लेकर प्रभावी कार्ययोजना लागू करनी होगी ताकि बाढ़ की स्थिति में पानी को बचाया जा सके और सूखे के समय उपयोग किया जा सके। पर्वतीय राज्यों में अधिक वर्षा से होने वाले भूस्खलन की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों और मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। सामान्य से अधिक वर्षा को केवल एक प्राकृतिक घटना मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। यह हमारे लिए चेतावनी भी है कि हम प्रकृति के दोहन और जलवायु असंतुलन को गंभीरता से लें। हमें आपदा प्रबंधन, टिकाऊ कृषि पद्धतियों, मजबूत मौसम पूर्वानुमान तंत्र, और हरित आवासीय योजनाओं की ओर बढ़ना होगा। तभी हम इस तरह की अतिवृष्टि को आपदा के बजाय अवसर में बदल सकते हैं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि सभी राज्य अपने बाढ़ प्रबंधन, राहत वितरण और पुनर्वास योजनाओं को तत्काल प्रभाव से क्रियान्वित करें ताकि सामान्य से अधिक वर्षा का प्रतिकूल प्रभाव जनजीवन और अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम हो।

सियासी गहमागहमी

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चल रही खींचतान

भाजपा में इन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर ऐसी खींचतान चल रही है, जैसे शादी में हलवाई के यहां जलेबी खत्म हो गई हो और सामने बैठा हर रिश्तेदार 'मेरे लिए बचा के रखना' कह रहा हो। आलम यह है कि पार्टी के हर वरिष्ठ नेता के चेहरे पर 'मैं ही अध्यक्ष बनूं' वाली मुस्कान चिपकी हुई है। कोई मंदिर में नारियल चढ़ा रहा है, कोई हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहा है, तो कोई अपने समर्थकों को ट्विटर पर लगातार 'जय श्रीराम' लिखवा रहा है, ताकि हाईकमान को उसकी भक्ति का प्रमाण मिलता रहे। वैसे, अध्यक्ष पद का मोह भी बड़ा चित्रविचित्र होता है। मंत्री, सांसद, विधायक – सब बन चुके लोग भी अध्यक्ष पद के लिए उतने ही लालायित रहते हैं, जितना बेरोजगार युवक पहली नौकरी के लिए। इस पद में रसूख है, टिकट बांटने का सुख है, और कैमरों की चकाचौंध में 'जनता जनार्दन' को संबोधित करने का मौका है। कहते हैं अध्यक्ष बनने के बाद आदमी के बोलने का लहजा भी बदल जाता है। वही व्यक्ति, जो कल तक "भाई साहब नमस्ते" कहता था, आज "देखिए पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है" कहने लगता है। आखिर राजनीति में पद मिलना भी तो किसी अच्छे मुहूर्त जैसा ही होता है – कब किसका तारा चमक जाए, कोई नहीं जानता।

बेटे चैतन्य को छुड़वाने भूपेश बघेल ने लगाई गुहार

कहते हैं, राजनीति में हर चीज का इलाज आलाकमान के दरबार में ही छुपा होता है। अब देखिए न, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद सीधे दिल्ली दरबार पहुंच गए। आलाकमान भी परेशान है। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि यह मामला भ्रष्टाचार का है, साजिश का है, सत्ता परिवर्तन का है या फिर 'बेटा बिगड़ गया' का पारिवारिक प्रकरण। उधर बघेल के चेहरे पर पिता का दर्द और नेता का धैर्य दोनों एकसाथ चमक रहे हैं। कह रहे हैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी कुछ तो करिए, बच्चा है। अब कौन समझाए कि बच्चा तो था, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त वयस्क निकला। वैसे, कांग्रेस में यह दृश्य नया नहीं है। जब भी किसी का मामला फंसता है, तो आलाकमान की चौखट पर माथा टेकना जरूरी होता है। सुना है भूपेश बघेल ने आलाकमान को ये भी याद दिलाया। देखिए, जब-जब मैंने छत्तीसगढ़ से आम भेजे थे, तब-तब आप बहुत खुश हुए थे। अब भी एक पेटी आम की भिजवा दूंगा, बस बेटे को छुड़वा दीजिए।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

SC केस 13 की परीक्षा में शामिल आ रही गड़बड़ियां सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि मोदी सरकार के विफल और सड़े हुए सिस्टम का आईना है। 400–500 किलोमीटर दूर से परीक्षा देने पहुंचे युवाओं को केंद्र पर जाकर पता चलता है कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। सिस्टम की खामियों के कारण लगातार पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से लाखों युवाओं और उनके परिवारों की मेहनत, समय और उम्मीदें बर्बाद हो रही हैं।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। प्रदेश में करीब 10 लाख बच्चे कुपोषित हैं और 1.36 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हैं।

कुपोषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने सभी कलेक्टरों से पांच लाख के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष @OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

राजनीतिक असंतुलन और आंतरिक संघर्षों के बावजूद कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे सचिन पायलट

समता पाठक/जगत प्रवाह

कांग्रेस नेता सचिन पायलटका जन्म 7 सितंबर 1977 को सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। पिता राजेश पायलट एक प्रतिष्ठित कांग्रेस कार्यकर्ता एवं केंद्रीय मंत्री थे। सचिन पायलट ने एयर फोर्स बाल भारती स्कूल, नई दिल्ली से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) से अंग्रेजी साहित्य में B.A. की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात I.M.T. गाजियाबाद से मार्केटिंग में डिप्लोमा और Wharton School ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूएसए से MBA किया है। सचिन पायलट ने 15 जनवरी 2004 को सारा अब्दुल्ला (पूर्व जम्मू-कश्मीर मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की पुत्री) से विवाह किया। सचिन पायलट ने राजनीति में कदम रखा जब उनके पिता राजेश पायलट का जून 2000 में एक कार दुर्घटना में देहांत हो गया। उस समय उन्होंने कांग्रेस परिवार की राजनीतिक विरासत को संभालने का निर्णय लिया।

2004 में मात्र 26 वर्ष की आयु में उन्होंने राजस्थान के दौसा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव जीता और भारत के सबसे युवा सांसद बने। 2009 में उन्होंने अजमेर संसदीय क्षेत्र से फिर से लोकसभा चुनाव जीता और दो बार सांसद बने। लोकसभा सांसद रहते हुए सचिन पायलट ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं बाद में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में उन्होंने Company Act 2013 पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कंपनियों के लिए अनिवार्य CSR प्रावधान शामिल थे, जो अब सामाजिक विकास में बड़े योगदान दे रहे हैं।

12 जुलाई 2020 को सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें उन्होंने लगभग 30 विधायक का समर्थन प्राप्त होने का दावा किया। इसके परिणामस्वरूप 14 जुलाई 2020 को उन्हें उप मुख्यमंत्री पद और राज्याध्यक्ष पद से हटा दिया गया; बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय में उन्होंने विधायकों की अयोग्यता के नोटिस को चुनौती दी। इसके बाद दो पक्षों समर्थक और गहलोत समर्थक में संगठन फिर से एकजुट हुआ। 14 अगस्त 2020 को विधानसभा में विश्वास मत से सरकार बची रही। सितंबर–अक्टूबर 2022 में फिर एक संकट आया। जब गहलोत समर्थक विधायक अचानक त्यागपत्र देने गए थे। इसे द्वितीय राजनैतिक संकट माना गया। सचिन पायलट का राजनैतिक सफर केवल एक विरासत संभालने की कहानी नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, युवा नेतृत्व, सामाजिक समर्पण और नीति-निर्माण का संयोजन है। अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लोक सेवाओं, तकनीकी सेवाओं का विस्तार, ग्रामीण विकास, और युवा सशक्तिकरण की दिशा में समर्पित कार्य किया है। राजनीतिक असंतुलन और आंतरिक संघर्षों के बावजूद, वे एक प्रमुख कांग्रेस नेता एवं राजस्थान के प्रभावशाली चेहरे बने। उनका व्यक्तित्व जो संवेदनशील भी है और निर्णायक भी। उनकी राजनीतिक यात्रा में अद्वितीय रहा है।

कहीं शिवराज सिंह चौहान पर की गई टिप्पणी के बाद दबाव में आकर तो धनखड़ ने नहीं दिया इस्तीफा

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पदों को पूरी तरह से सियासत से रखना चाहिए दूर

(पेज 1 का शेष)

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह इन पदों को भी राजनीतिक दबाव में लाने की कोशिशें होती रही हैं, धनखड़ का इस्तीफा उसी का परिणाम माना जा रहा है। अगर उपराष्ट्रपति जैसा पद भी स्वतंत्र निर्णय न ले सके तो यह लोकतंत्र के संतुलन के लिए खतरे की घंटी है। इससे संसद की स्वायत्तता, उच्च सदनों की गरिमा और संविधान की मूल भावना कमजोर हो सकती है।

धनखड़ का राजनीतिक सफर और भाजपा से रिश्ता

जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के किसान परिवार में हुआ। पढ़ाई के बाद उन्होंने वकालत में करियर शुरू किया और फिर जनता दल के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 1990 में वीपी सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने। इसके बाद वे धीरे-धीरे भाजपा के करीब आए और पार्टी में मजबूत स्थान बनाते चले गए। 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। ममता बनर्जी सरकार के साथ उनकी तीखी टकराहटों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बना दिया। उनके कड़े तेवरों, संविधान का सटीक ज्ञान और संवाद शैली के कारण भाजपा नेतृत्व ने 2022 में उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और वे निर्विरोध चुने भी गए।

मोदी सरकार के लिए असहज सवाल

उनके इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह केवल व्यक्तिगत असंतोष का मामला था या इसके पीछे भाजपा नेतृत्व से नाराजगी और प्रशासनिक दबाव का पहलू भी जुड़ा था? सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों से धनखड़ अपने संवैधानिक अधिकारों के उपयोग और राज्यसभा में स्वायत्तता के मुद्दों को लेकर परेशान थे। उपराष्ट्रपति के तौर पर उनकी जिम्मेदारी राज्यसभा के सभापति की भी है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों और कुछ भाजपा नेताओं का लगातार हस्तक्षेप उन्हें खलने लगा था। हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जब उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मंच से ही अनुशासन और मर्यादा की हिदायत दी, तो यह साफ संकेत था कि उनका असंतोष केवल आंतरिक ही नहीं, सार्वजनिक रूप से भी व्यक्त होने लगा था। इसके बाद से ही उनके और पार्टी नेतृत्व के रिश्तों में तनाव की चर्चाएं तेज थीं।

भाजपा के भीतर के समीकरण

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि धनखड़ भाजपा के उस पुराने वैचारिक समूह का प्रतिनिधित्व करते थे, जो संगठन, अनुशासन और वैचारिक पृष्ठभूमि को सर्वोपरि मानता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भाजपा के भीतर जिस तरह का 'हाईकमान कल्चर' बढ़ा है, उसमें नेताओं की स्वतंत्रता सीमित होती गई है। धनखड़ जैसे स्पष्टवादी नेता के लिए यह स्थिति स्वीकार्य नहीं रही। यही कारण है कि उन्हें बार-बार राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना पड़ा। एक अन्य वर्ग का मानना है कि धनखड़ को भाजपा में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से आगे के किसी पद पर अवसर नहीं दिख रहा था। उनकी महत्वाकांक्षाओं को पंख नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में इस्तीफे का फैसला उन्होंने भविष्य की नई राजनीतिक पारी के रूप में लिया हो सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक तो यह भी कह रहे हैं कि वे विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकते हैं, क्योंकि उनकी किसान पृष्ठभूमि और भाजपा की कार्यप्रणाली के प्रति उनका असंतोष विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार साबित हो सकता है।

कौन हो सकता है अगला उपराष्ट्रपति

धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब यह भी सवाल उठने लगे हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? भाजपा नेतृत्व के पास कई नाम चर्चा में हैं। इनमें असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता थावरचंद गहलोत, भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर, महाराष्ट्र की राज्यपाल रमेश बैस और पार्टी के कद्दावर आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा के नाम प्रमुख हैं। वहीं, एक वर्ग यह भी मानता है कि भाजपा दक्षिण भारत से किसी नेता को उपराष्ट्रपति बनाकर 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए दक्षिण भारत की रणनीति को धार दे सकती है। तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश से भी कुछ वरिष्ठ नामों पर विचार चल रहा है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से टकराव का प्रसंग

धनखड़ और शिवराज सिंह चौहान के बीच हालिया टकराव की घटना भी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मंच पर ही शिवराज सिंह को अनुशासन में रहने की नसीहत दे दी थी। सूत्रों के मुताबिक यह प्रसंग तब हुआ जब शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में देरी पर मंच से ही टिप्पणी कर दी, जिसे उपराष्ट्रपति ने पद की गरिमा के विरुद्ध माना। उन्होंने मंच से ही कहा– "मंत्री जी, मर्यादा का पालन करना हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है।" इस सार्वजनिक फटकार के बाद ही भाजपा नेतृत्व और धनखड़ के रिश्तों में दरार की बातें सामने आने लगी थीं।

धनखड़ ने दी थी चेतावनी

पिछले साल एक तरफ हरियाणा पंजाब की सीमा पर किसान आंदोलन कर रहे थे तो दूसरी ओर दिल्ली-नोएडा की सीमा पर भी प्रदर्शन जारी थे। इन प्रदर्शनों के बीच ही धनखड़ ने सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ कोई बातचीत क्यों नहीं हुई? उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि उनसे पहले किए गए वादों का क्या हुआ। धनखड़ ने यह भी कहा कि किसानों के मुद्दों की अनदेखी करना दोषपूर्ण नीति निर्धारण को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने केंद्र से किसानों की चिंताओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने की अपील की। धनखड़ मुंबई में केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीआईआरसीओटी) से जुड़े एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां पर उनके साथ कृषि मंत्री भी थे। धनखड़ ने इसी समारोह में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कुछ चुभने वाले सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, 'कृषि मंत्री जी, क्या आपसे पहले जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? अगर वादा किया था तो उसका क्या हुआ?' धनखड़ ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि किसानों धैर्य की परीक्षा न ले।

भविष्य की संभावनाएं

राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि धनखड़ का इस्तीफा भाजपा के लिए सतर्कता का संकेत है। पार्टी नेतृत्व को यह समझना होगा कि हर वरिष्ठ नेता केवल आदेश का पालन करने के लिए नहीं बना। कुछ नेता विचारधारा, स्वाभिमान और संविधान की मर्यादाओं को सर्वोपरि रखते हैं। यदि ऐसे नेताओं को दरकिनार किया जाएगा तो पार्टी की बौद्धिक और वैचारिक पूंजी कमजोर होगी। वहीं, विपक्ष के लिए यह सुनहरा अवसर है। यदि धनखड़ विपक्ष के साथ आते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का उम्मीदवार बनाकर भाजपा के लिए एक नैतिक संकट पैदा किया जा सकता है। धनखड़ की छवि सशक्त वक्ता, संविधान विशेषज्ञ और किसान हितैषी नेता के रूप में है, जिसका लाभ विपक्ष लेने की कोशिश करेगा। हालांकि अभी उन्होंने अपने भविष्य की राजनीतिक रणनीति को सार्वजनिक नहीं किया है।

भाजपा की अंतर्कथा को किया उजागर

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा न केवल भाजपा के भीतर की अंतर्कथा को उजागर करता है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए भी एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। क्या हम अपने संविधान के सर्वोच्च पदों की गरिमा को राजनीतिक दबावों से सुरक्षित रख पा रहे हैं? धनखड़ का यह फैसला बताता है कि जब तक संवैधानिक पदों की स्वायत्तता, गरिमा और निष्पक्षता को महत्व नहीं दिया जाएगा, तब तक देश में लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखना मुश्किल होगा। भाजपा को भी इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि वह अपने उन नेताओं को कैसे सम्मान दे, जिन्होंने संगठन को खड़ा किया और जिनका कद पार्टी की शक्ति का आधार रहा है। फिलहाल, पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं कि धनखड़ का अगला कदम क्या होगा और भाजपा इस संकट को कैसे संभालती है। क्योंकि यह इस्तीफा महज एक पद से नहीं, बल्कि भाजपा की कार्यशैली और भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना से जुड़ा गंभीर संदेश भी है।

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं का यौन उत्पीड़न एवं आत्महत्याएं

इसे उच्च शिक्षा संस्थानों की विडंबना ही कहा जाएगा कि अब तक गुरुओं की प्रताड़ना के चलते शिष्यों की आत्महत्याओं के मामले सामने आते रहे हैं, किंतु अब अपनी पुत्री समान छात्राओं के साथ दुष्कर्म के मामले भी सिलसिलेवार सामने आ रहे हैं। ओड़ीसा के बालासोर में यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कार्यवाही न होने से परेशान छात्रा ने आत्मदाह कर लिया। इसी तरह चेन्नई में दो शिक्षक हवस पूर्ति के लिए हैवान बन गए। इन शिक्षकों ने छात्रा को नोट्स देने के लिए बुलाया और दुष्कर्म किया। कोलकाता के आईआईएम की एक मनोवैज्ञानिक महिला परामर्शदाता के साथ छात्रावास में कथित दुष्कर्म का मामला भी सामने आया है। उच्च शिक्षा परिसरों के ये मामले चिंता के साथ शर्मसार करने वाले हैं। इन संस्थानों में प्रताड़ना के चलते आत्महत्या के मामले भी नहीं थम रहे हैं। नोएडा के शारदा विश्वविद्यालय में दंत चिकित्सा की छात्रा ने छात्रावास के अपने कक्ष में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। छात्रा द्वारा आत्महत्या से पहले लिखे पत्र में विवि के डीन एम सिद्धार्थ, प्राध्यापक सैरी मैडम, मोहंद्र, अनुराग अवस्थी, आशीष कुमार एवं सुरभि को प्रताड़ना का दोषी ठहराया है। पुलिस ने मोहंद्र एवं सैरी को गिरफ्तार कर लिया है। विवि प्रशासन ने इन दोनों के अलावा अन्य तीन प्राध्यापकों को निलंबित कर दिया है।

यह अत्यंत बेचैन करने वाला विषय है कि उच्च शिक्षा के लिए हम विदेशी विवि भारत में खोलने के फैसले ले रहे हैं, दूसरी ओर हम अपनी शिक्षा संबंधी नीतियों में पश्चिम का जरूरत से ज्यादा अनुकरण कर रहे हैं। जबकि हमें अपने ही संस्थानों में बुनियादी सुधार की जरूरत है। यदि हम विदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे तो छात्र एवं अभिभावक देसी संस्थानों को दोयम दर्जे

शिक्षा संस्थानों में संभावनाओं की मौत

का मानने लग जाएंगे। वैसे भी विदेशों में पढ़ाई के चलते प्रतिभाओं के पलायन का संकट खड़ा हो रहा है। शिक्षकों द्वारा दुष्कर्म और प्रताड़ना के बढ़ते मामलों से तय होता है कि एक तो हमारे शिक्षक वैभव और भोग की हसरतें पालने लगे हैं, दूसरे ये छात्रों में उम्मीदों की उड़ान पैदा करने की बजाय निराशा, कुंठा और अवसाद पैदा कर रहे हैं। लगता है शिक्षकों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी कोई उत्साहजनक असर नहीं पड़ा है। अन्यथा इस तरह की शर्मसार कर देने वाली घटनाएं घटती ही नहीं।

21वीं सदी को ज्ञान की सदी की संज्ञा दी गई है। ज्ञान परंपरा और मातृभाषाओं में शिक्षा दिए जाने की बात भी खूब जोर-शोर से उठी है। शिक्षा की पूंजी से गरीब और वंचित के लिए उच्च पद, बड़ा उद्योगपति और विश्वस्तरीय तकनीकिशियन (टेक्नोक्रेट) बनने के रास्ते भी खुले हैं। बावजूद शिक्षा संस्थाओं से दुष्कर्म, पलायन और आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं तो यह चिंतनीय पहलू है। क्योंकि शिक्षा के जरिए विद्यार्थी और उसके अभिभावक जिस उपलब्धि के शिखर पर पहुंचने की परिकल्पना कर रहे होते हैं, यदि इसी बीच संभावना की मौत हो जाए, तो यह शिक्षा का अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। ज्ञान की महिमा ने इस भ्रम को तोड़ने का काम किया है कि शिक्षा पर जाति, नस्ल या रक्त विशेष समुदायों का ही अधिकार है। राजतंत्र में यह धारणा सदियों तक फलीभूत होती रही है कि भारत समेत दुनिया का कुलीन वर्ग नियति की देन है। जबकि वास्तविकता यह पक्षपाती व्यवस्था की उपज रही है। ज्ञान के तंत्र ने इस भ्रामक स्थिति को तोड़ने का काम किया है। हालांकि भारतीय मनीषियों ने ज्ञान की इस शक्ति को हजारों साल पहले जान लिया था, इसीलिए कहा भी गया कि राजा की पूजा अपने राज्य में होती है, जबकि विद्वान सब जगह पूजा जाता है। ज्ञानार्जित विद्वता की ही देन है कि आज दुनिया शिक्षा और अनुसंधान से आविष्कृत ऐसा तकनीकि संसार रच रही है, जिसमें सुविधाएं मुट्ठी में हैं और लक्ष्य अंतरिक्ष में मनुष्य को बसाने की संभावनाएं तलाश रहा है। संभावनाओं के इस द्वार पर शिक्षा परिसरों में छात्र निराशा के भंवर में मौत का लक्ष्य तय कर रहे हैं, तो यह समूची शिक्षा पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह है?

देश के युवाओं की ये मौतें, संभावनाओं की मौतें हैं। ऐसे में यदि छात्र एवं छात्राओं की मौतों का यही सिलसिला बना रहता है तो देश के बेहतर भविष्य की संभावना क्षीण हो जाएगी ? ये मौतें अध्ययन-अध्यापन से उपजी परेशानियों के चलते सामने आ रही हैं। बावजूद देखने में आ रहा है कि राजनीतिक दलों के रहनुमा मौतों को केवल राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, लिहाजा समस्या के समाधान की दिशा में ठोस पहल होती नहीं दिख रही है। यदि आने वाले समय में छात्र आत्महत्याओं को शिक्षा की व्यापक समझ के परिदृश्य में नहीं देखा गया तो इन मौतों पर विराम लग जाएगा यह कहना मुश्किल है? देश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च व तकनीकी शिक्षा तक शिक्षण पद्धति को लेकर अजीब भ्रम, विरोधाभास व दुविधा की स्थिति बनी हुई है। नतीजतन इनसे उबरने के अब तक जितने भी उपाय सोचे गए, वे शिक्षा के निजीकरण, अंग्रेजीकरण और विदेशीकरण पर जाकर सिमटते रहे हैं। यही वजह रही कि देश में शिक्षा में आवश्यक बदलाव लाने की दृष्टि से आयोग तो बिठाए गए, उनकी रपटें भी आईं, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। लिहाजा शिक्षा प्रणाली में आदर्श व समावेशी शिक्षा के बुनियादी तत्व में शामिल करने की बजाय, शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो केवल और केवल अंग्रेजीकरण की पर्याय बनती जा रही है। नतीजतन शिक्षा सफलता के ऐसे मंत्र में बदल गई है, जिसका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना रह गया है। दुष्चक्र में फंसी इस शिक्षा की यही खामियां इन घटनाओं में देखने में आ रही हैं।

कोटा के कोचिंग संस्थानों में निरंतर छात्रों द्वारा की जा रही खुदकुशियों की पड़ताल करने से पता चलता है कि छात्रों को अभिभावक अपनी इच्छा के अनुसार महान बनाने की होड़ में लगे हैं। केरल के रहने वाले छात्र अनिल कुमार ने आत्महत्या पूर्व लिखे पत्र में लिखा था, 'सॉरी मम्मी-पापा, आपने मुझे जीवन दिया, लेकिन मैंने इसकी कद्र नहीं की।' यह पीड़ादायी कथन उस किशोर का था, जो आईआईटी की तैयारी में जुटा था। ये संस्थान प्रतिभाओं को निखारने का दावा अपने विज्ञापनों में खूब करते हैं। लेकिन युवाओं को महान और बड़ा बनाने का सपना दिखाने का इस उद्योग का दावा कितना खोखला है, यह पता यहां बढ़ती जा रही आत्महत्याओं से चलता है। शिक्षा के इस कोचिंग उद्योग का गोरखधंधा देशव्यापी है। इसकी जकड़न में अब अन्य प्रदेशों के बड़े नगर भी आते जा रहे हैं।

एम्स भोपाल की 3डी प्रिंटिंग लैब से चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में एम्स भोपाल स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देते हुए निरंतर प्रगति कर रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2024 में स्थापित "कम्प्यूटेशनल 3डी मॉडलिंग एंड प्रिंटिंग लैब" अब चिकित्सा, अभियांत्रिकी और डिजिटल डिजाइन के संगम पर विकसित होता हुआ एक उभरता राष्ट्रीय नवाचार केंद्र बन चुका है। यह अत्याधुनिक प्रयोगशाला पॉलीजेट डिजिटल एनाटॉमी प्रिंटर, हाई-परफॉर्मेंस वर्कस्टेशन्स और उन्नत मॉडलिंग सॉफ्टवेयर से सुसज्जित है, जिसकी मदद से अत्यंत सटीक, यथार्थवादी और रोगी-विशिष्ट शारीरिक संरचनाएं तैयार की जाती हैं। इन संरचनाओं का उपयोग न केवल पूर्व-शल्य योजना और सर्जिकल प्रशिक्षण में हो रहा है, बल्कि दुर्लभ रोग मामलों के संग्रह, रोगी परामर्श और मेडिकल छात्रों के शिक्षण में भी किया जा रहा है। इससे चिकित्सकीय निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार और अंतरविभागीय ज्ञानवर्धन को बल मिल रहा है।

मस्जिद के पास खुदाई में मिला 16वीं-17वीं सदी का शिवलिंग

-संवाददाता

जगत प्रवाह. विदिशा। पुरातत्व की धरोहर कहे जाने वाले विदिशा जिले के उदयपुर कस्बे में मस्जिद के पास खोदाई करते समय एक 16वीं-17वीं शताब्दी के शिवलिंग मिलने की सूचना मिलने पर पुरातत्व विभाग सहित स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार उदयपुर गांव में चौखंडी वाली मस्जिद के पास गुरुवार सुबह खोदाई के दौरान एक प्राचीन शिवलिंग मिला। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को जानकारी दी। अधिकारी पुरातत्व विभाग के साथ मौके पर पहुंचे और शिवलिंग को पूरी तरह मिट्टी से बाहर निकाला। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने बताया की जमीन में मिला शिवलिंग 16वीं-17वीं शताब्दी का है। इसकी ऊंचाई लगभग 3 फीट है। जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है, वहां निजाम नामक व्यक्ति अपने भवन का निर्माण करवा रहा था। इसी दौरान शिवलिंग दिखाई दिया।

ग्रीन डे एवं मैंगो डे मनाया गया

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। दिनांक 22 जुलाई को वर्षा ऋतु सावन के मौसम में गीता निकेतन कोल्ड स्कूल टिमरनी के द्वारा स्कूल में बच्चों के साथ ग्रीन डे एवं मैंगो डे मनाया गया जिसमें बच्चों ने कार्ड सीट पर फलों की आकृति आम की आकृति आदि बनाकर लाये जिस पर स्कूल टीचर के द्वारा पेड़ों से हमें क्या-क्या प्राप्त होता है जैसे पेड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, फल प्राप्त होते है, कुछ पौधों से औषधि भी तैयार की जाती है। पौधे लगाने से उन्हें फल प्राप्त होता है एवं पौधों के माध्यम से धरती का नदियों का कटाव रोका जाता है आदि। चीजों की जानकारी दी गई एवं बच्चों को अधिक से अधिक पौधे लगाने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर स्कूल संचालक डॉ. गणेश पाटील निशा पाटील जैनु लोबसी, ममता भार्गव, पूजा अग्रवाल, निर्मला कौशल, भावना कुशल, वर्षा मालवीय, योगिता मालाकार, सिया परदेसी आदि स्टाफ उपस्थित रहा।

भूमिगत जल को विषैला बना रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग "मिथक या सच"

पर्यावरण की फ़िक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

दिल्ली की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में लगे वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) उपकरण बारिश का पानी बचा तो रहे हैं, लेकिन इससे भूजल दूषित हो रहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को सौंपी रिपोर्ट में यह जानकारी दी थी। डीपीसीसी ने कहा कि वर्षा जल बचाने के लिए बनाए गए गड्ढे का डिजाइन दोषपूर्ण होने से इसमें सीवेज का पानी मिल रहा है, इससे भूजल दूषित हो रहा है। डीपीसीसी ने दिल्ली के द्वारका में 176 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में लगे वर्षा जल संचयन उपकरणों के सर्वे के आधार पर रिपोर्ट तैयार की। एनजीटी प्रमुख जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली बेंच को डीपीसीसी ने रिपोर्ट सौंपी दी है। बहुत जगहों पर देखा गया है कि नगर निगम द्वारा रेनवाटर हार्वेस्टिंग पिट में सीवर का पानी जोड़ दिया जाता है जिससे धरती के गर्भ का पानी विषैला होता जा रहा है जो बहुत चिंता का विषय है।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आम तौर पर भूमिगत जल स्तर को सुधारने का एक बेहतरीन साधन माना जाता है। यह प्रथा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बढ़ती जल समस्याओं का हल मानी जाती है, क्योंकि इससे गिरते भूजल स्तर में सुधार आता है। परंतु, यदि इसे लापरवाही और बिना सही तकनीक के लागू किया जाए तो यही रेन वाटर हार्वेस्टिंग भूमिगत जल को विषैला बना सकती है। जब बरसात का पानी छतों या अन्य सतहों से होकर निकलता है, तो उसके साथ धूल, पत्तियाँ, केमिकल, और भारी धातुएँ भी मिल सकती हैं, खासकर यदि छतें या हार्वेस्टिंग सिस्टम गंदे हों या उनमें कोई फिल्टरिंग सिस्टम न लगा हो। शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के कारण बारिश का पानी एसिडिक भी हो सकता है, जिसमें लेड (Pb), जिंक, या अन्य भारी धातुएँ घुल सकती हैं। ये प्रदूषक बारिश के साथ भूमिगत जल में चले जाते हैं। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम को समय-समय पर साफ नहीं किया जाए, तो विभिन्न बैक्टीरिया, केमिकल और अन्य हानिकारक तत्व भी भूजल में मिश्रित हो सकते हैं, जिससे भूजल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

कई बार कृषि रसायन, जैसे कि कीटनाशक या उर्वरक, भी बरसाती पानी के साथ जमीन में घुलकर भूजल तक पहुँच जाते हैं, यदि फिल्टरिंग का ठीक इंतजाम न हो। जिंक वाली पुरानी छतों से लेड या अन्य हानिकारक धातुएँ भी बरसात के पानी में आ सकती हैं, जो लंबी अवधि में छात्रों और आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा, अगर स्टोरेज टैंक या रिचार्ज वेल्स को ढंका न रखा जाए तो इनके अंदर सूक्ष्मजीव और गंदगी भी प्रवेश कर सकते हैं, जिससे जल जनित रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। कभी-कभी लीकेज या खराब प्लानिंग के कारण बारिश का पानी सीवेज से मिल जाता है, जिससे पानी में और भी ज्यादा प्रदूषण फैल सकता है।

इन सभी जोखिमों से बचने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सही तकनीक और नियमित सफाई के साथ संचालित करना बहुत जरूरी है। छतों एवं पाइपों की समय-समय पर सफाई, अच्छे फिल्टर का उपयोग और उचित टैंक कवरिंग से इन समस्याओं को रोका जा सकता है। जगह-जगह कराए गए सफल प्रोजेक्ट्स ने साबित किया है कि जब तकनीक सही हो और नियमों का पालन किया जाए, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से केवल फायदा ही मिलता है, नुकसान नहीं। आखिर में, यह कहना गलत नहीं होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्वयं में भूमिगत जल को विषैला नहीं बनाती, बल्कि लापरवाही और सही रख-रखाव की कमी ही असली जड़ है। सही जागरूकता और सावधानी से न केवल भूजल की। गुणवत्ता बनाए रखी जा सकती है, बल्कि सतत विकास के लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ!

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर अब थम गया है, परिणाम सामने हैं और कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया पूरे ज़ोरों पर है। जहाँ कुछ युवाओं को उनके मनपसंद कॉलेज और कोर्स मिल गए हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो अपनी उम्मीदों के मुताबिक सफलता न मिलने से थोड़े निराश हैं। आज हम इन्हीं युवाओं से बात करेंगे। याद रखिए, जीवन संभावनाओं से भरा है। अपनी कथित असफलता को एक अनुभव के तौर पर लें और इससे सीखकर सफलता की ओर बढ़ें। खुद से बस इतना कहें: "मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ।" सवाल यह नहीं है कि आप सफल हुए या नहीं, सवाल यह है कि आप सीखकर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। इस साल मध्य प्रदेश में विभिन्न स्तरों की परीक्षाओं और उनके परिणामों ने हजारों छात्रों के जीवन में नए मोड़ लाए हैं। ये परिणाम सिर्फ अंकों का खेल नहीं, बल्कि अनुभव, धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा भी हैं। याद रखिए, जीवन कभी रुकता नहीं; यदि एक दरवाज़ा बंद होता है, तो दूसरा हमेशा खुलता है। यदि आपका चयन इस बार नहीं भी हो पाया है, तो इसे एक रुकावट नहीं, बल्कि रणनीति को फिर से सोचने का मौका समझें। यह समय है अपनी गलतियों से सीखने का, अपनी कमज़ोरियों पर काम करने का, और अपनी राह को और मजबूत बनाने का। आपकी दुनिया यहीं नहीं रुकेगी; बल्कि यह एक नई शुरुआत है, जहाँ आप और भी बेहतर होकर आगे बढ़ेंगे।

हर चुनौती में छिपा होता है एक और अवसर

दसवीं और बारहवीं की पूरक परीक्षा के रूप में लाखों छात्रों को एक और मौका दिया, यह साबित करते हुए कि एक असफलता कभी भी अंत नहीं होती। 17 जून से 5 जुलाई 2025 तक हुई इन परीक्षाओं के माध्यम से कई छात्रों ने हिम्मत नहीं हारी और अब वे इसे पास करने के बाद गर्व के साथ कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं। यह उनकी दृढ़ता और इच्छाशक्ति का प्रमाण है कि उन्होंने एक नया रास्ता बनाया। याद रखिए, जीवन कभी रुकता नहीं; यदि एक दरवाजा बंद होता है, तो दूसरा हमेशा खुलता है।

JEE (Mains & Advanced) और NEET जैसी चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में सफल हुए छात्र काउंसलिंग के ज़रिए प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। यदि आप पीछे रह गए हैं, तो निराश न हों! यदि आपका चयन इस बार नहीं भी हो पाया है, तो इसे एक रुकावट नहीं, बल्कि रणनीति को फिर से सोचने का मौका समझें। एक परीक्षा में पिछड़ना आपके सपने को खत्म नहीं करता, बल्कि यह उसे और मजबूत करता है। यह आपको सिखाता है कि आपको कहाँ और कैसे सुधार करना है। यह समय है अपनी गलतियों से सीखने का, अपनी कमजोरियों पर काम करने का, और अपनी राह को और मजबूत बनाने का। आपकी दुनिया यहाँ नहीं रुकेगी; बल्कि यह एक नई शुरुआत है, जहाँ आप और भी बेहतर होकर आगे बढ़ेंगे। आप इससे सीखकर और भी मजबूत इरादों के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। यह दुनिया आगे बढ़ेगी, और आप भी, नए अवसरों और बेहतर तैयारियों के साथ!

अब क्या करें- अपनी सीख को दिशा बनाएं

- आप काउंसलिंग प्रक्रिया में सतर्क रहें, समय पर सही विकल्प चुनें।
- कॉलेज का चुनाव करते समय सिर्फ रैंक या नाम न देखें, अपनी रुचि और संस्थान की विशेषज्ञता को प्राथमिकता दें।
- उच्च शिक्षा का यह नया अध्याय आपकी खुद की पहचान और आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम है। आप इसे मजबूती से उठाएं।
- यदि परिणाम अपेक्षित नहीं रहा: यह हार नहीं, सीखने का मौका है!
- आप अन्य विकल्पों (डिप्लोमा, स्किल कोर्स, फॉर्म भरने के नए मौके, निजी संस्थान आदि) को तलाशें।
- अगली परीक्षा की तैयारी ठोस प्लानिंग से करें, पिछली गलती दोहराएं नहीं।
- और सबसे जरूरी- खुद पर विश्वास बनाए रखें।

प्रवेश प्रक्रिया में यह बातें ध्यान रखें:

- जरूरी दस्तावेज (आधार, अंकसूची, फोटोज आदि) एक जगह व्यवस्थित रखें।
- काउंसलिंग और एडमिशन की अंतिम तिथियाँ नोट करें।
- मार्गदर्शन के लिए शिक्षकों या काउंसलरों से बातचीत करें।
- कोर्स फीस और अन्य खर्चों के लिए बजट प्लानिंग करें।

ज़िंदगी में हर परिणाम एक पड़ाव है, मंज़िल नहीं

जीवन की सफलता सिर्फ परीक्षा पास करने में नहीं, असफलता से दोबारा उठ खड़े होने में है। जो छात्र आज कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं, उन्हें सजग, जिम्मेदार और केंद्रित रहना चाहिए। और जो अभी अपने लक्ष्य से दूर हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि हर सपना समय मांगता है- हार नहीं और जो समय देता है, वही जीत के योग्य बनता है।

औद्योगिक नीति

अब और अधिक रोजगारपरक, व्यापक और उद्यमों के लिए लाभकारी

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

- **स्थानीय युवाओं** को रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष अनुदान
- **आधुनिक खेती** से लेकर खिलौना उद्योग तक को मिलेगा बढ़ावा
- **वस्त्र क्षेत्र में निवेश** पर अब 200 फीसदी तक का प्रोत्साहन
- **ग्लोबल कैपेबिलिटी** सेंटर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज
- **पर्यटन और होटल** व्यवसाय को बढ़ावा
- **नीति में संशोधन** से युवाओं, किसानों, उद्यमियों और निवेशकों को सीधा लाभ

R.O. No. : 13331/ 1

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)